गोयल की निवेश और उद्योग सहयोग बैठकें

भारत-मेक्सिको आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर

'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 22 मार्च : भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठकें कीं. सबसे पहले उन्होंने मेक्सिको के अर्थव्यवस्था सचिव मार्सेलो एब्रार्ड से मुलाकात की. बातचीत में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने, निवेश और व्यापार के नए अवसर खोलने और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के रास्तों पर चर्चा हुई.

गोयल ने अमेरिका की दवा कंपनी एली लिली के प्रतिनिधि पैट्रिक जॉनसन से भी मुलाकात की. इसमें भारत में कंपनी की बढ़ती मौजूदगी, निवेश और 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' पहल को मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श हुआ.

इसके अलावा ग्रीस के उप विदेश मंत्री हैरी थियोहारिस के साथ बैठक में भारत और ग्रीस के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर चर्चा हुई.

स्टार्टअप और युवा उद्यमिता को भी इस बातचीत में खास स्थान मिला. गोयल ने ज़ेप्टो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित पलिचा के साथ युवा कौशल विकास, नवाचार और आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में किसानों के एकीकरण के तरीकों पर चर्चा की.

भारत की तेजी से बढ़ती स्टार्टअप पारिस्थितिकी, नवाचार और वैश्विक निवेश आकर्षण को देखते हुए, इन बैठकों से व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

> गोयल ने सभी बैठकों को 'उत्पादक' बताते हुए साझा किया कि यह वार्तालाप भारत की वैश्विक आर्थिक भागीदारी और निवेश को और मजबूत करेगी. इन बैठकों का उद्देश्य भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश के केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और उद्योग, स्टार्टअप और युवा कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना है.

चावल, गेहूं, खाद्य तेल, दालों के दाम बढ़े

नयी दिल्ली, 22 मार्च . घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ गेहूं, खाद्य तेल और दालों में भी तेजी रही. वहीं, चीनी में गिरावट का रुख देख गया. सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 26 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,809 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 25 रुपये महंगा होकर 2,819 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटे का भाव सात रुपये गिरकर 3,294 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. दालों की कीमत में भी तेजी रही. सप्ताह के दौरान तुअर दाल की औसत कीमत 103 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. उड़द दाल 99 रुपये और मूंग दाल 53 रुपये महंगी हुई. चना दाल का भाव 21 रुपये और मसूर दाल का आठ रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा.

आरबीआई की नई रणनीति-उत्कर्ष 3 .0

नई दिल्ली/पटना, 22 मार्च. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट और उत्कर्ष 3.0 रणनीति फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है. यह रणनीति अगले तीन वर्षों के लिए बैंक की नीतिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय करेगी, जिसमें वित्तीय स्थिरता, नियामक सुधार और संस्थागत दक्षता बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य हैं.

आरबीआई बोर्ड की 622वीं बैठक पटना में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य, भू-राजनीतिक घटनाओं और उनके वित्तीय बाजारों पर प्रभाव का आकलन किया और उससे जुड़े जोखिमों पर विचार कर बजट और रणनीति को अंतिम रूप दिया.

> एसजीएस नीलामी में अधिकतम अवधि 23 साल तक रही, जो लंबी अवधि के राज्य ऋण साधनों में निवेशकों की रुचि को दर्शाती है . इन पहलों से राज्य सरकारों की वित्तीय गतिशीलता बढ़ी है और निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर पैदा हुए हैं . आरबीआई बोर्ड का यह कदम बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के साथ ही आर्थिक नीतियों में स्थिरता बनाए रखने का संकेत देता है . उत्कर्ष 3 .0 के माध्यम से बैंक अगले तीन वर्षों में वित्तीय स्थिरता और संस्थागत दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा, जिससे भारतीय वित्तीय प्रणाली और अधिक टिकाऊ बन सके .

उत्कर्ष 3.0 फ्रेमवर्क आरबीआई की पिछली रणनीतिक पहलों का विस्तार करता है और अगले तीन सालों में वित्तीय प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने, नियामक तंत्र को सुधारने और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा.

शेयर बाजारों पर जारी रहेगा वैश्विक कारकों का असर

मुंबई, 22 मार्च बीते सप्ताह मामूली बदलाव के बाद आने वाले सप्ताह में भी घरेलू शेयर बाजारों पर वैश्विक कारकों का असर जारी रहेगा.

निवेशकों की नजर पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की कीमतों पर रहेगी. साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था पर पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव का भी वे आंकलन कर रहे हैं. अभी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद का कोई वृहद आर्थिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन युद्ध से पहले फरवरी में आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में सुस्ती देखी गयी है.

पिछले सप्ताह बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहा. पांच कारोबारी दिवसों में से चार में प्रमुख सूचकांक हरे निशान में रहे, लेकिन गुरुवार की सवा तीन फीसदी की गिरावट के कारण साप्ताहिक आंकड़े नकारात्मक रहे. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 30.96 अंक (0.04 प्रतिशत) की साप्ताहिक गिरावट में शुक्रवार को 74,532.96 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी सप्ताह के दौरान 36.60 अंक यानी 0.16 फीसदी टूटकर 23,114.50 अंक पर रहा. मझौली कंपनियों का निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.32 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त में बंद हुआ. स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 1.11 प्रतिशत की गिरावट रही. बीते सप्ताह सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल का शेयर 7.55 प्रतिशत, टाटा स्टील का 7.25, टेक महिंद्रा का 3.98, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3.87 और अल्ट्राटेक सीमेंट का 3.02 प्रतिशत मजबूत हुआ.

> एचडीएफसी बैंक का शेयर 4.47 प्रतिशत, हिंदुस्तान यूनीलिवर का 3.55 और बीईएल का 3.08 प्रतिशत लुढ़क गया. बजाज फाइनेंस में 2.88 फीसदी, बजाज फिनसर्व में 1.66 प्रतिशत, सनफार्मा में 1.28 और पावरग्रिड में 1.06 प्रतिशत की गिरावट रही. एनटीपीसी, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी के शेयर भी लाल निशान में रहे.

वैश्विक आपूर्ति संकट की आशंका, भारत पर पड़ेगा असर : रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 22 मार्च. खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और संभावित व्यवधानों के कारण कई प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर सेमीकंडक्टर और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है. डैम कैपिटल एडवाइजर्स की एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गयी है. रिपोर्ट के अनुसार, हीलियम, सल्फर, मेथनॉल और एल्युमिनियम जैसी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे सेमीकंडक्टर निर्माण, उर्वरक और निर्माण जैसे उद्योगों पर असर पड़ेगा. उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा आने से कृषि लागत बढ़ सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की उपलब्धता अल्पावधि में संभालने योग्य रह सकती है.

स्थिति चुनौतीपूर्ण, लेकिन सरकार पर विश्वास

नयी दिल्ली, 22 मार्च भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने रविवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन सरकार द्वारा किया जा रहे प्रयासों के कारण देश इन झटकों से उबरने में कामयाब रहेगा.

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत मूकदर्शक बनकर नहीं बैठा है, बल्कि अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ले रहा है और रोजगार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहा है. सरकार ने इन परिस्थितियों में उद्योगों को मदद देने के लिए कई उपाय किये हैं. खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए सरकार निरंतर दूतावासों के माध्यम से सहायता मुहैया करा रही है.

उद्योगों को मदद देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं

कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों की कमी से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित

श्री बनर्जी ने कहा, '...हालांकि स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, हमें विश्वास है कि सरकार का समग्र दृष्टिकोण और सभी हितधारकों के साथ उसकी साझेदारी-आधारित सहभागिता देश को इस झटके से उबरने और अपनी आर्थिक प्रगति को बनाये रखने में मदद करेगी.'

उन्होंने कहा कि चुनौती बड़ी है और सीआईआई सरकार और उद्योग के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों की निगरानी, कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों की कमी को दूर करने का काम जारी रखे हुए है.

बयान में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी ईरान युद्ध के कारण महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाधित हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा बाजारों तथा आयात-निर्यात पर दबाव है. भारतीय कंपनियां भी इससे अछूती नहीं हैं. एक ओर शिपमेंट में देरी हो रही है और दूसरी तरफ प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं. कई क्षेत्रों में आवश्यक कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों की कमी हो गयी है.

एफपीआई ने मार्च माह में निकाले 1 .05 लाख करोड़

डेट में 13,754 करोड़ रुपए और हाइब्रिड में 471 करोड़ बिकवाली

म्यूचुअल फंड में उनका निवेश 2,911 .27 करोड़ रुपए कम हुआ

मुंबई, 22 मार्च विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च के पहले तीन सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से शुद्ध रूप से 1,05,316 करोड़ रुपये निकाले हैं.

इससे पहले निवेशक फरवरी में शुद्ध रूप से लिवाल रहे थे, यानी उन्होंने जितना पैसा लगाया था उससे कम निकाला था.

एफपीआई ने मार्च में इक्विटी में अपना निवेश 88,180 करोड़ रुपये घटा दिया जो दिखाता है कि भारतीय शेयरों में अभी उनका विश्वास नहीं है. डेट, म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड उपकरणों में भी उनका निवेश नकारात्मक रहा है.

डेट में उन्होंने शुद्ध रूप से 13,754 करोड़ रुपये और हाइब्रिड में 471 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है. म्यूचुअल फंड में उनका निवेश 2,911.27 करोड़ रुपये कम हुआ.

इससे पहले फरवरी में एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार में 37,847 करोड़ रुपये लगाये थे.

1 अप्रैल से नए टैक्स नियम लागू

सैलरीड कर्मचारियों पर दो बड़े बदलाव का असर

नई दिल्ली, 22 मार्च: अगले वित्त वर्ष 2026 से भारतीय इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव आने वाले हैं. सरकार ने इनकम-टैक्स रूल्स 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो पारदर्शिता, डिजिटल रिपोर्टिंग और अनुपालन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

सैलरीड कर्मचारियों के लिए ये बदलाव खास हैं, क्योंकि दो बड़े नियम सीधे उनके टैक्स के बोझ को प्रभावित करेंगे.

सबसे पहले, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अब कंसेशनल परक्विजिट वैल्यूएशन रूल्स में शामिल किया गया है. इससे कंपनियों और कर्मचारियों को प्रतिमाह कुछ हज़ार रुपये का टैक्स-फायदा मिलेगा. कंपनियों द्वारा खर्च उठाने पर प्रतिमाह 5000 और ड्राइवर के लिए 3000 तक लाभ मिलेगा. वहीं यदि कर्मचारी खुद खर्च उठाते हैं तो 2000 और ड्राइवर के लिए 3000 का लाभ होगा. दूसरा, हाउस रेंट अलाउंस की छूट अब कुछ नए शहरों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में भी बढ़ा दी गई है.

मेहसाणा में आरओबी सर्वे, कनेक्टिविटी मजबूत

ओल्ड विसनगर रोड से ओल्ड पाटन रोड जुड़ेगा, यातायात होगा सुगम

अहमदाबाद , 22 मार्च. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल और मेहसाणा महानगरपालिका ने शहर में प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण के लिए विस्तृत ग्राउंड सर्वे किया. इस पहल का उद्देश्य यात्रियों और आम नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है.

प्रस्तावित आरओबी ओल्ड विसनगर रोड को ओल्ड पाटन रोड से जोड़ेगा. साथ ही यह अहमदाबाद-पालनपुर हाईवे से पुलिस मु यालय तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. इस पुल की कुल लंबाई लगभग 1050 मीटर होगी, जिसमें 76 मीटर का गर्डर स्पैन और 12 मीटर चौड़ाई का प्रावधान रखा गया है.

उल्लेखनीय है कि रेलवे लाइन के मीटर गेज से ब्रॉड गेज में रूपांतरण के बाद मेहसाणा शहर दो हिस्सों में बंट गया था, जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही थी. इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में आरओबी परियोजना तैयार की गई है.सर्वेक्षण के दौरान सांसद हरिभाई पटेल, राज्यसभा सांसद मयंकभाई नायक, मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश, जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैस्मीन सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

उपचुनाव का शंखनाद : भाजपा ने उतारे धुरंधर

पोंडा से बागलकोट तक किसे मिला टिकट?

नई दिल्ली. देश के राजनीतिक नक्शे पर एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा ने गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पार्टी ने लोकल और फेमस चेहरों पर दांव लगाया है.

इन राज्यों की पांच महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा ने अपने 'योद्धाओं' के नाम तय कर दिए हैं, जो स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुने गए हैं. यह चुनाव केवल एक सीट जीतने की कवायद नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय के लिए जनता के मूड को भांपने का एक बड़ा जरिया भी साबित होगा.

देश के अलग-अलग हिस्सों में खाली पड़ी विधानसभा सीटों को भरने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है. सूत्रों के मुताबिक, यह उपचुनाव मुख्य रूप से मौजूदा विधायकों के असामयिक निधन के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, नागालैंड में पूर्व मंत्री इम्कोंग एल. इम्चेन और त्रिपुरा के वरिष्ठ नेता बिस्वा बंधु सेन के निधन से ये सीटें खाली हुई थीं. इन चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान 9 अप्रैल को निर्धारित किया गया है, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी.

> **भाजपा ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल**
>
> भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय संगठन की राय को उपर रखा है . गोवा की राजनीति की बात करें, तो यहां की पोंडा सीट (सीट नंबर 21) से रितेश रवि नायक को चुनावी मैदान में उतारा गया है . कर्नाटक में भी भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए अनुभवी और लोकप्रिय नामों पर भरोसा जताया है . बागलकोट से वीरभद्रय्या चारंतिमठ और दावणगेरे दक्षिण से श्रीनिवास टी . दासकरियप्पा को टिकट दिया गया है .

हुड्डा ने जैसे-तैसे बचाई इज्जत

चंडीगढ़. हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार करमबीर बौद्ध चुनाव जीत गए हैं. वे बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीते क्योंकि कांग्रेस के पांच विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि चार विधायकों के वोट अवैध हो गए.

देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कांग्रेस नेताओं ने दबाव बनाया तब जाकर एक विधायक की वोट को मान्यता दी गई अन्यथा वह भी अवैध हो रही थी. इसी तरह भाजपा का भी एक वोट अवैध हुआ तब जाकर 28 वोट पर बौद्ध की जीत हुई.

सोचें, हरियाणा में कांग्रेस के 37 विधायक हैं और चुनाव जीतने के लिए 31 वोट की जरुरत थी. इंडियन नेशनल लोकदल के दो विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो जीत का आंकड़ा 30 पर आ गया. लेकिन 37 विधायकों वाली पार्टी के उम्मीदवार को 28 वोट मिले. इसके लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरा जोर लगाना पड़ा. 78 साल के हुड्डा खुद इलेक्शन एजेंट बने थे और हर विधायक पर नजर रख हुए थे. असल में राहुल गांधी ने उम्मीदवार ऐसा चुना कि उसका जीतना पहले ही नामुमकिन हो गया था. करमबीर बौद्ध कांग्रेस से नहीं जुड़े थे. प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि राहुल किसी बाहरी को उम्मीदवार न बनाएं.

जेडीएफ को मंजूरी से राजनीति में नया मोड़

जम्मू. जम्मू-कश्मीर की सियासत बड़ा ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है, यहां सालों से अलगाववादी सोच से जुड़े रहे नेता अब लोकतांत्रिक राजनीति में खुलकर उतर रहे हैं.

इसी कड़ी में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े कई प्रमुख चेहरों ने 'जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट' (जेडीएफ) के रूप में नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, जिसे चुनाव आयोग से आधिकारिक पंजीकरण मिल गया है. इस कदम को न सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव, बल्कि प्रदेश की राजनीति में संभावित बड़े फेरबदल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ये नेता लंबे वक्त तक मुख्यधारा की राजनीति से दूरी बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का फैसला किया है. नई पार्टी जेडीएफ ने साफ किया है कि वह भारतीय संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी और विकास, न्याय व जनहित के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाएगी.

यह बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पहले जमात-ए-इस्लामी सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेती थी. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन का परोक्ष प्रभाव कई बार चुनावों में देखा गया, जहां उसने कुछ दलों या उम्मीदवारों को समर्थन दिया. अब जब उससे जुड़े नेता खुद राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं, तो यह स्थिति पूरी तरह बदल सकती है. एक्सपर्ट्स की माने तो, जेडीएफ के गठन से जम्मू-कश्मीर के चुनावी समीकरणों पर असर पड़ना तय है. इससे न सिर्फ ट्रेडिशनल राजनीतिक दलों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, बल्कि नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल सकती है. खासकर उन क्षेत्रों में, जहां जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव रहा है, वहां यह पार्टी मजबूत चुनौती पेश कर सकती है.

आतंकी संगठनों का कैडर भी जमात से...

बता दें कि कश्मीरी आतंकियों के बड़े आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात-ए-इस्लामी का फौजी बाजू भी कहा जाता रहा है . उसका अधिकांश कैडर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से जमात से संबंधित है . जमात भी पहले कभी जम्मू-कश्मीर की चुनावी राजनीति में भाग लेती थी . 1989 के बाद से वह कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार करती रही है . वह वर्ष 2003 तक हुर्रियत कान्फ्रेंस के प्रमुख घटकों में एक रही है .

विशेष अकोला जिला प्रमुख समेत 4 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे का थामा हाथ

शिवसेना उद्धव का ढहा किला

अकोला. अकोला महानगर पालिका चुनाव की हलचल शांत होते ही अब अकोला में शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) गुट को बड़ा झटका लगा है. वर्तमान जिला प्रमुख सहित 4 पार्षदों ने शिवसेना उबाठा छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का रुख किया है. मंगलवार, 17 मार्च की रात मुंबई में यह घटनाक्रम हुआ और बुधवार को अकोला में इसकी खबर फैलते ही राजनीतिक हलचल मच गई हैं.

अब अकोला में उबाठा गुट के पास केवल दो पार्षद ही बच गए हैं, जिससे 80 सदस्यीय महानगर पालिका में उनकी ताकत न के बराबर हो गई है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रमुख उपस्थिति में मुंबई में शिवसेना उबाठा गुट के जिला प्रमुख मंगेश काले तथा चार पार्षद मनोज पाटिल, सागर भारुका, सोनाली सरोदे और सुरेखा काले ने शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश किया.

अकोला महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना उबाठा गुट ने महाविकास आघाड़ी से अलग होकर स्वबल पर 54 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 6 सीटों पर विजय हासिल हुई. अब इनमें से 4 पार्षदों के अलग होने से गुट को बड़ा नुकसान हुआ है. महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने भी स्वबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें केवल 1 सीट पर सफलता मिली.

भाजपा के साथ सत्ता में आने के बाद अब 4 नए पार्षदों के जुड़ने से उनकी संख्याबल 5 तक पहुंच गयी है और मनपा में उनका प्रभाव बढ़ने वाला है.

मंगेश काले को मिलेगा जिला प्रमुख पद?- इस राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी के अनुसार, शिवसेना उबाठा गुट के जिला प्रमुख मंगेश काले को अब शिवसेना शिंदे गुट का जिला प्रमुख पद मिलने की चर्चा है. साथ ही पार्षदों को उनके प्रभागों के विकास के लिए भरपूर निधि देना भी तय होने की जानकारी मिली है.

> **शिवसेना उबाठा गुट के पास केवल दो पार्षद**
>
> महानगर पालिका चुनाव में इस बार तस्वीर बदलने की स्थिति बनाने वाले उबाठा गुट को अपेक्षित सफलता नहीं मिली . कई सीटों पर उन्हें बहुत कम अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि 6 सीटों पर विजय प्राप्त हुई . इन 6 में से 4 पार्षदों ने अब साथ छोड़ दिया है, जिससे उबाठा गुट के पास केवल 2 पार्षद ही बच गए हैं . इनमें पार्षद अभय खुमकर और विजय इंगले का समावेश है .